पूरी बेंच

एसएस संधावालिया से पहले, सीजे, डीएस तेवतिया और एसपी गोयल, जे जे।

मैम राज,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

*सिविल रिट याचिका संख्या*1981 का 2332

27 जनवरी 1982

*पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम (XXV)*1961)—धारा 55—सहकारी समिति अपने सदस्य के माध्यम से अन्य सहकारी समिति के माध्यम से व्यवसाय करती है—सदस्य समिति एक सेल्समैन को नियुक्त करती है और उसके साथ व्यवसाय का कमीशन साझा करती है—सहकारी समिति और सदस्य समिति के सेल्समैन के बीच विवाद -क्या धारा 55(1)(बी) के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है - सेल्समैन - क्या किसी सदस्य के माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति कहा जा सकता है' - धारा 55 - का उद्देश्य - बताया गया है।

आयोजित,(प्रति बहुमत एसएस संधवालिया, सीजे और डीएस तेवतिया, जे., एसपी गोयल जे., कॉन्ट्रा) कि यह स्पष्ट है कि जहां तक विवाद एक समाज के बीच का है! और इसके पिछले सदस्य चिंतित हैं कि वे स्पष्ट रूप से वैधानिक मध्यस्थता के दायरे में हैं। हालाँकि, विधायिका ने जानबूझकर इसे तब बढ़ाया जब उसने गैर-सदस्यों को भी अपने दायरे में लाने के लिए 'किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करना* वाक्यांश का इस्तेमाल किया। स्पष्ट रूप से रखी गई योग्यता या सीमा यह है कि ऐसे गैर-सदस्य को या तो किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करना चाहिए और 'आवश्यक परिणाम के रूप में उनके माध्यम से उत्तरदायी होना चाहिए क्योंकि यदि कोई किसी के माध्यम से दावा करता है तो अपरिहार्य कानूनी परिणाम होंगे। वह उसके माध्यम से समान रूप से जवाबदेह होगा.. 'किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करना' शब्द केवल हित के हस्तांतरण के मामलों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए और परिणामस्वरूप उन्हें केवल उत्तराधिकारी-हित, उत्तराधिकारियों को शामिल करने तक सीमित नहीं किया जा सकता है। 'या कानूनी प्रतिनिधि। वाक्यांश की ऐसी कृत्रिम और संकुचित व्याख्या क़ानून के बड़े उद्देश्य के विपरीत होगी। धारा 55 की उपधारा (1) का खंड (सी) नामांकित व्यक्तियों, 'उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों' की बात करता है। इस प्रकार विधायिका इस पदावली के प्रति सक्रिय रूप से सचेत थी और यदि यह इरादा था कि दावा केवल नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि आदि के माध्यम से होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वही शब्दावली खंड (बी) में भी नियोजित की गई होगी। ये शब्द कला और विधायिका के प्रसिद्ध शब्द हैं। जानबूझकर 'दावा' और 'के

माध्यम से' शब्दों का उपयोग करने के लिए चुना गया और इसलिए, इसे व्यापक सामान्य आयाम की भाषा में जोड़ा गया। वहाँ
ऐसे सदस्य या पूर्व सदस्य के हितों के हस्तांतरण या हितों के उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों आदि की दूर तक सीमित और सीमित अवधारणाओं तक इन शब्दों के स्पष्ट और सामान्य अर्थ को कम करने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक सहकारी समिति और उसके सदस्य समिति के बीच विवाद स्पष्ट रूप से धारा 55(1) (बी) के अंतर्गत आता है क्योंकि यह एक समिति और उसके सदस्य के बीच उत्पन्न होता है। एक बार ऐसा होने पर, 'सहकारी समिति' का अपने सदस्य समिति के सेल्समैन के खिलाफ उसका एजेंट या भागीदार के रूप में दावा एक सदस्य के माध्यम से किया गया दावा होगा। यह तर्कसंगत प्रतीत होता है कि एक बार एक सहकारी समिति और उसके सदस्य समिति के बीच वैधानिक संदर्भ सक्षम हो जाता है, तो सदस्य समिति के माध्यम से निहित कमीशन या अन्य दायित्व जैसे जुड़े दावे भी खंड (बी) के दायरे में होने चाहिए। धारा 55(1). इस प्रकार, एक ओर सहकारी समिति और दूसरी सहकारी समिति के कर्मचारी, एजेंट या सदस्य के बीच विवाद, धारा 55(1) (बी) के तहत मध्यस्थता के दायरे में होगा, जहां किया गया दावा है किसी व्यक्ति या समाज के माध्यम से निहित होता है जो बदले में दावेदार-समाज का सदस्य होता है।

(पैरा 13, 14, 15 और 25;

*इंदरजीत सिंह*हरियाणा राज्य,
1981 की सिविल रिट संख्या 414, 23 मार्च 1981 को निर्णय हुआ।

ओवरर ने शासन किया.

आयोजित(प्रति एसपी, गोयल, जे., कॉन्टा) कि "सदस्य के माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति" शब्द का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे सदस्य के माध्यम से अधिकार या स्वामित्व का दावा करता है। जहां एक सहकारी समिति, सहकारी समिति के एक सदस्य के माध्यम से व्यापार करती है, जो बदले में बिक्री पर अर्जित कमीशन के भुगतान पर एक सेल्समैन को नियुक्त करता है, तो सहकारी समिति और ऐसे सेल्समैन के बीच कोई विवाद नहीं होगा। अधिनियम की धारा 55 (1) के खंड (बी) द्वारा कवर किया गया। सदस्य सोसायटी ने सेल्समैन के साथ अपने समझौते से कभी भी सहकारी समिति के साथ समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार या देनदारियों को हस्तांतरित नहीं किया। सदस्य सोसायटी के साथ अपने समझौते के आधार पर, सेल्समैन ने 'दो सोसायटी के बीच अनुबंध के तहत कोई अधिकार या दायित्व हासिल नहीं किया' और इस प्रकार वह न तो बिक्री आय के लिए सहकारी सोसायटी को खाते देने के लिए उत्तरदायी था और न ही अपना दावा करने का हकदार था। इसमें से कमीशन का हिस्सा. उसे केवल अधिकृत एजेंट के रूप में कार्य करना था और सदस्य समाज द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए उसे पुरस्कृत किया जाना था। क्योंकि, अपने स्तर पर कर्तव्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कदाचार या दुराचार के लिए, वह केवल अपने नियोक्ता या प्रिंसिपल, यानी, सदस्य समाज के प्रति जवाबदेह था। चूंकि वह दो समाजों के बीच समझौते के तहत कुछ भी दावा नहीं कर सकता है, इसलिए उसे "सदस्य के माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति" नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, धारा 55 की उप-धारा (1) के खंड (बी) द्वारा कवर नहीं किया जाएगा। अधिनियम का.

(पैरा 31 एवं 33)।

आयोजित(प्रति एसएस संधवालिया सीजे, और डीएस तेवतिया, जे.) कि अधिनियम

की धारा 55 को अधिनियमित करने में विधायिका का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि एक बार जब कोई विवाद सहकारी समिति के संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय को छूता है तो ऐसी सहकारी समिति सोसायटी, उसके सदस्यों, पूर्व सदस्यों और उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों, साथ ही अधिकारियों, एजेंटों या कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और परिसमापक जिनमें उनके नामांकित व्यक्ति, कानूनी प्रतिनिधियों के उत्तराधिकारी आदि (विस्तृत हुए बिना) को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और इससे बचाया जाना चाहिए। ऐसे विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से सामान्य नागरिक मुकदमे की लंबी और जटिल प्रक्रिया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वैधानिक मध्यस्थता का त्वरित और सस्ता उपाय अन्य सभी उपायों को छोड़कर प्रदान किया जाता है। धारा 55 की उपधारा (1) का अंतिम भाग स्पष्ट शब्दों में यह प्रावधान करता है कि ऐसी स्थिति में किसी भी न्यायालय के पास ऐसे विवाद के संबंध में किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इस स्थिति को और दोहराने के लिए, अनुभाग। 82(सी) ओह अधिनियम यह प्रावधान करता है कि किसी भी नागरिक या राजस्व न्यायालय के पास धारा 55 के तहत रजिस्ट्रार या एवी मामले को संदर्भित करने के लिए आवश्यक एवी विवाद के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा जिसमें धारा 55-ए के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि यहां वैधानिक प्रावधान का पूरा जोर धारा 55 में सूचीबद्ध पक्षों को केवल वैधानिक मध्यस्थता के दायरे में लाने से लेकर सिविल और राजस्व न्यायालयों के संपूर्ण बहिष्कार तक के लिए है। संपूर्ण धारा 55 के 1 फ्रेम पर फिर से एक व्यापक नज़र डालने से सुरक्षा के इस क्षेत्र का विस्तार करने और विवाद की प्रकृति के साथ-साथ इसके पक्षों के संबंध में सिविल और राजस्व न्यायालयों के बहिष्कार के लिए विधायिका की चिंता प्रदर्शित होती है। इसलिए, यह उचित प्रतीत होता है कि इस क़ानून के बड़े उद्देश्य को शाब्दिक या संकुचित व्याख्या के विपरीत आगे बढ़ाने के लिए खंड 55 की भाषा पर खंडन की प्रकृति और उसके पक्षों की संख्या दोनों के संबंध में एक उदार निर्माण किया जाना चाहिए। उसके
(पैरा 11, 12 एवं 13)।

*अनुच्छेदों के अंतर्गत याचिका*भारत के संविधान के 226/227 में प्रार्थना की गई है कि सहायक रजिस्ट्रार का आदेश, दिनांक 14 जनवरी, 1980, और संयुक्त सचिव का आदेश, दिनांक 19 मई। 1981, अवैध एवं बिना अधिकार क्षेत्र के होने के कारण निरस्त किया जा सकता है।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि मामले/रिट के लंबित रहने के दौरान विवादित आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जा सकती है।

जीएस संधू. याचिकाकर्ता के लिए वकील।

प्रतिवादी की ओर से प्रेम सिंह, अधिवक्ता, सीआर दहिया, अधिवक्ता।

प्रलय

एसएस संधावालिया, सीजे

(1) क्या एक ओर सहकारी समिति और दूसरी सहकारी समिति (किसी सदस्य के माध्यम से दावा) के कर्मचारी, एजेंट या सदस्य के बीच विवाद धारा 55(1) (बी) के तहत

मध्यस्थता के दायरे में है) पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 - वह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके कारण पूर्ण पीठ द्वारा इस रिट याचिका पर सुनवाई करना आवश्यक हो गया है। हालांकि प्रस्ताव के स्तर पर इस न्यायालय के भीतर मिसाल के तौर पर कुछ विसंगतियां भी मुद्दे पर हैं।

(2) मैम राज याचिकाकर्ता इम्बली को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड के सेल्समैन के रूप में काम कर रहे थे, जो जगाधरी को-ऑपरेटिव मार्केटिंग जी-कम-प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जगाधरी (इसके बाद 'मार्केटिंग सोसाइटी' कहा जाएगा) से उर्वरक खरीदती थी। , खेप के आधार पर। मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा देय ऐसे उर्वरकों की बिक्री पर इम्बली को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड (बाद में इसे इम्बली सोसाइटी कहा जाएगा) द्वारा अर्जित कमीशन को याचिकाकर्ता और इम्बली सोसाइटी द्वारा समान रूप से साझा किया गया था। मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, इम्बली सोसायटी के बीच उर्वरकों पर कमीशन के भुगतान के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ और मामला पंजाब कंपनी की धारा 55 के तहत मध्यस्थता के लिए सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, यमुनानगर को भेजा गया था। -ऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1961 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा)। मध्यस्थ ने उसमें एक पुरस्कार प्रदान किया, जिसे बाद में सिविल कोर्ट ने रद्द कर दिया, इसके बाद, मार्केटिंग सोसाइटी ने रुपये का दावा करते हुए एक और मध्यस्थता की मांग की। याचिकाकर्ता से 16,721 रु. इन कार्यवाहियों में नियुक्त मध्यस्थ ने याचिकाकर्ता के साथ-साथ मुस्तफा-बैड फार्मर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ संयुक्त रूप से और अलग-अलग अपना फैसला, अनुलग्नक पी/एल दिया, इस निर्देश के साथ कि राशि सबसे पहले वसूल की जाएगी। याचिकाकर्ता और यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो इसे मुस्तफाबाद फार्मर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड से वसूल किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने उक्त पुरस्कार के खिलाफ अपील की और अन्य बातों के साथ-साथ यह रुख अपनाया कि कोई मध्यस्थता नहीं! एक ओर मार्केटिंग सोसायटी और दूसरी ओर याचिकाकर्ता के बीच सुनवाई योग्य थी, क्योंकि वह उक्त सोसायटी का सदस्य नहीं था। हालाँकि, सरकार के संयुक्त सचिव ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया, - अनुबंध पी/3 के माध्यम से। वर्तमान रिट याचिका हग

उक्त पुरस्कार के खिलाफ प्राथमिकता दी गई थी और मुख्य रूप से इस आधार पर दबाया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मध्यस्थता का कोई वैध संदर्भ नहीं दिया जा सकता था। प्रस्ताव चरण में, यह देखा गया कि इस मुद्दे पर खंड पीठ के फैसले विरोधाभासी थे और इसलिए, रिट याचिका को पूर्ण पीठ द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया। जे ।

(3) जैसा कि मोशन बेंच के सामने है, वैसे ही हमारे सामने, याचिकाकर्ता की ओर से लगाई गई प्राथमिक और वास्तव में एकल चुनौती मध्यस्थता के संदर्भ की वैधता के खिलाफ है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता मार्केटिंग सोसायटी का सदस्य नहीं होने के कारण,

अधिनियम की धारा 55 के तहत मध्यस्थता का कोई वैध संदर्भ उसके खिलाफ नहीं दिया जा सकता है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के लिए मध्यस्थ और अपीलीय मंच के समक्ष कार्यवाही दूषित हो गई।

(4) उपरोक्त विवाद की सराहना करने के लिए, पहले तथ्यात्मक मैट्रिक्स को स्पष्ट करना सबसे अच्छा है। यह विवादित नहीं है कि इम्बली सोसाइटी प्रतिवादी नंबर 4. द मुस्तफाबाद फार्मर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड (इसके बाद इसे 'मुस्तफाबाद सोसाइटी' कहा जाएगा) के साथ मिल गई है। समान रूप से, यह स्वीकृत स्थिति है कि इम्बली सोसाइटी और मुस्तफाबाद सोसाइटी स्वयं प्रतिवादी नंबर 3, मार्केटिंग सोसाइटी के सदस्य थे। प्रतिवादी का दृढ़ रुख यह है कि 'जहां तक उसके और इम्बली सोसाइटी के बीच उर्वरकों की बिक्री पर कमीशन आदि के मुनाफे के बंटवारे का सवाल है, याचिकाकर्ता ने इम्बली सोसाइटी के भागीदार के रूप में काम किया। अपीलीय प्राधिकारी का निष्कर्ष, विस्तृत अनुबंध पी/3 यह भी है कि याचिकाकर्ता इम्बली सोसाइटी की ओर से और उसके एक भागीदार के रूप में कार्य कर रहा था।

5. आगे बढ़ने से पहले यह याद रखना भी उतना ही उपयुक्त है कि अधिनियम की धारा 30 के तहत, इसके तहत पंजीकृत प्रत्येक सोसायटी शाश्वत उत्तराधिकार के साथ एक कॉर्पोरेट निकाय है। नतीजतन, यह अपने स्वयं के कानूनी व्यक्तित्व से ओत-प्रोत है। इसलिए, स्थापित सिद्धांतों पर, एक सहकारी समिति एक कानूनी व्यक्ति है जिसका व्यक्तिगत कॉर्पोरेट अस्तित्व उसके व्यक्तिगत सदस्यों से अलग और अलग होता है, चाहे वे प्राकृतिक व्यक्ति हों या अन्य कॉर्पोरेट निकाय हों। सोसायटी और उसके घटक सदस्यों के कानूनी व्यक्तित्व के बीच इस अंतर को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बहुत

5-ए. अनिवार्य रूप से, यहां विवाद अधिनियम की धारा 55 और विशेष रूप से उसकी उपधारा (1) की भाषा के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे शुरुआत में ही पढ़ा जा सकता है -

"55. वे विवाद जिन्हें मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है,

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सहकारी समिति के संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है-

(a) सदस्यों, पूर्व सदस्यों और सदस्यों, पूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच, या

(b) किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या किसी सदस्य, पूर्व सदस्य* या मृतक के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति और सोसायटी, उसकी समिति या सोसायटी के किसी अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी या परिसमापक, अतीत या वर्तमान के बीच, या

(c) ■ सोसायटी या उसकी समिति और किसी पिछली समिति, किसी अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी, या किसी पूर्व अधिकारी, पिछले एजेंट या पिछले कर्मचारी या किसी मृत अधिकारी के नामित, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधियों के बीच, मृत एजेंट-या सोसायटी के मृत कर्मचारी, या

(d) सोसायटी और किसी अन्य सहकारी सोसायटी के बीच, एक सोसायटी और दूसरी सोसायटी के परिसमापक के बीच या एक सोसायटी के परिसमापक और दूसरी सोसायटी के परिसमापक के बीच।

ऐसे विवाद को निर्णय के लिए रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा और किसी भी अदालत को ऐसे विवाद के संबंध में किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

*****»

65 अब उपरोक्त प्रावधानों का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य यह संकेत देगा कि- इसके प्रावधानों के दायरे में रहने के लिए, दो पूर्व शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले, विवाद की प्रकृति के संबंध में। यह कोई एक और हर विवाद नहीं है जो

क़ानून के तहत संदर्भ का विषय-वस्तु हो सकता है। जिन विवादों को संदर्भित किया जाता है, उनका दायरा ऐसा बताया जाता है जो किसी सहकारी समिति के संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय को छूता है। यह पहलू विवाद की प्रकृति की गुणात्मक स्थिति बताता है। चलते-चलते यह ध्यान देना होगा कि 'विवाद' शब्द[4]जैसा कि: क़ानून में उपयोग किया गया है, जाहिरा तौर पर एक व्यापक श्रेणी है। यह आवश्यक नहीं है कि ढाका को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल यूनियन बनाम ढाका को-ऑपरेटिव सांख्य सुपा समिति लिमिटेड और अन्य (1) मामले में देखे गए किसी उचित या कानूनी रूप से वैध विवाद की कल्पना निम्नलिखित शब्दों में की जाए: -

> "……यह दृष्टिकोण भी उतना ही अस्थिर है कि क्योंकि संघ का दावा ख़राब था या यहाँ तक कि झूठा था, इसलिए कोई विवाद नहीं था। हमारे निर्णय में विवाद तब तक रहेगा, जब तक किसी दावे पर एक पक्ष दावा करता है और दूसरा उसे अस्वीकार करता है, चाहे वह दावा झूठा हो या सच्चा, या अंततः वह झूठा या सच साबित होता है।''

समान रूप से वाक्यांश 'समाज के व्यवसाय को छूना' की व्याख्या चागला, जे. (जैसा कि वह तब था) ने जीआईपी, रेलवे कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम भीखाजी मेरवानजी करनपा, (2) में की है। इसे देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में, विवाद की प्रकृति अधिनियम की धारा 55 (1) के चारों कोनों के भीतर है।

7. अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) के खंड (ए), (बी), (सी) और (डी) ऐसे विवाद के पक्षों से निपटते हैं। एक बार जब विवाद की प्रकृति की पूर्व शर्त पूरी हो जाती है, तो अगली बात उसके पक्षकारों की होती है। ऐसा केवल तभी होता है जब वे चार खंडों के व्यापक दायरे में आते हैं (जो जानबूझकर व्यापक जाल डालने के लिए तैयार किए गए प्रतीत होते हैं) कि कोई विवाद रजिस्ट्रार द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

8. फिर से खंड (ए), (बी) और (सी) पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि मोटे तौर पर ये समाज और उसके सदस्यों, पिछले सदस्यों, मृत सदस्यों, अधिकारियों, एजेंटों या समाज के कर्मचारियों के बीच विवाद को एक डिजाइन के साथ दर्शाते हैं। गैर-सदस्यों के लिए विस्तार जो किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या के माध्यम से दावा कर रहे हों

4एआईआर 1938 कलकत्ता 327।

मृत सदस्य. यह स्पष्ट है कि यहां विधायिका ने गैर-सदस्यों को भी शामिल करने के लिए जानबूझकर दायरा बढ़ाया है, साथ ही यदि वे आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। इन तीन खंडों में उल्लिखित पक्षों की गणना से पता चलेगा कि यहां क़ानून द्वारा जो परिकल्पना की गई है वह (कला के शब्द का उपयोग करने के लिए) अंतर-समाज विवाद हैं।

9. दूसरी ओर खंड (डी) उन पार्टियों की कल्पना करता है जो अंतर-समाज हैं। ऐसा लगता है कि यह स्वतंत्र सहकारी समितियों के बीच या एक समिति और दूसरे के परिसमापक के बीच और यहां तक कि ऐसी दोनों समितियों के परिसमापक के बीच विवादों का प्रावधान करता है।

10. अब प्रतिवादियों की ओर से कड़ा रुख खंड (बी) की भाषा और विशेष रूप से 'किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति' वाक्यांश पर रहा है। उनके विद्वान वकील श्री प्रेम सिंह ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से इस शब्दावली के दायरे में आता है।

11. सामान्य तौर पर अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों और विशेष रूप से उसकी उपधारा (1) के खंड (बी) की व्याख्या करते समय, अधिनियम के बड़े उद्देश्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में कोई भी रसिकलाल बनाम कैलासगौरी (3) में डिवीजन बेंच के लिए बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश भगवती (जैसा कि वह तब थे) के बार-बार उद्धृत शब्दों को दोहराने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता: -

> “सहकारी समिति संगठन का एक रूप है जिसमें व्यक्ति सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। 'सहयोग' जैसा कि सीआर रे ने बताया है, 'कमजोरों के बीच संयुक्त व्यापार के उद्देश्य से एक संघ है और हमेशा निःस्वार्थ भावना से ऐसी शर्तों पर संचालित होता है कि जो लोग सदस्यता के कर्तव्यों को संभालने के लिए तैयार हैं वे इसके पुरस्कार साझा कर सकें उस डिग्री के अनुपात में जो वे अपने सहयोग का उपयोग करते हैं? यह अनिवार्य रूप से सीमित साधनों वाले व्यक्तियों का एक संघ है और, जैसा कि बॉम्बे सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1925 की प्रस्तावना में दर्शाया गया है, इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ 'का प्रचार करना' है।

कृषकों और सामान्य आर्थिक आवश्यकताओं वाले अन्य व्यक्तियों के बीच बचत, स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता।' यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है और यह मानते हुए स्वार्थी विशिष्टता से बचता है कि इसकी सदस्यता उन सभी के लिए खुली होनी चाहिए जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। संगठन के सहकारी रूप में मतदान की शक्ति संयुक्त स्टॉक कंपनी की तरह शेयरधारिता के अनुपात में नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक सदस्य को एक वोट दिया जाता है ताकि प्रबंधन में सभी की समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके, भले ही उनकी संपत्ति कुछ भी हो। . सहयोग एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादकों और उपभोक्ताओं को एक-दूसरे के करीब लाकर बिचौलिए को खत्म करने का भी प्रयास करता है और इसका उद्देश्य मजबूत लोगों द्वारा समुदाय के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकना है। यह उपभोक्ताओं सहित धन अर्जन में योगदान करने वाले सभी लोगों के लिए वितरणात्मक न्याय की वकालत करता है। यह संगठन का एक रूप है जो पूंजीवाद की बुराइयों से बचाता है और फिर भी व्यक्ति की मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करता है। इसीलिए इसे हमारे सामाजिक-आर्थिक ढांचे में पसंदीदा स्थान दिया गया है। इसलिए, इसके संबंध में कानून बनाने वाली विधायिका इसे वांछनीय समझ सकती है कि सहकारी समिति के गठन, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एक विशेष मशीनरी प्रदान की जानी चाहिए जो बहुत सरल और तेज होगी। सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय के सामान्य उपाय से कम महंगा। यह इस उद्देश्य से था कि विधानमंडल ने विवादित धारा को अधिनियमित किया। विवादित वर्गों द्वारा विशेष मशीनरी प्रदान करने का उद्देश्य विवादों का शीघ्र निपटारा करना, मुकदमेबाजी की लागत कम करना और प्रक्रिया के तकनीकी नियमों से बिना किसी बाधा के न्याय सुनिश्चित करना है ताकि सहकारी समितियां लंबे समय तक इसमें शामिल न हों। मुकदमेबाजी लंबी खिंच गई, जिसमें उनका समय, ऊर्जा और संसाधन खर्च होंगे। संगठन के सहकारी रूप की प्रकृति और चरित्र, जिन सिद्धांतों की स्थापना की गई है और जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका इरादा है, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह उद्देश्य संविधान से संबंधित विवादों के समाधान के लिए विशेष प्रक्रिया के आवेदन को पूरी तरह से उचित ठहराएगा, किसी समाज का प्रबंधन या व्यवसाय।

अधिनियम की धारा 55 को विशेष रूप से देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें विधायिका का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि एक बार जब कोई विवाद सहकारी समिति के संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय को छूता है तो ऐसी सहकारी समिति, सदस्यों, पूर्व सदस्यों और उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों, साथ ही अधिकारियों, एजेंटों या कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और परिसमापक जिनमें उनके नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि आदि भी शामिल हैं, (विस्तृत हुए बिना) को लंबे समय तक चलने वाले संकट से बचाया और बचाया जाना चाहिए। . और ऐसे विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से सामान्य नागरिक मुकदमे की जटिल प्रक्रिया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वैधानिक मध्यस्थता का त्वरित और सस्ता उपाय अन्य सभी उपायों को छोड़कर प्रदान किया जाता है। यह दोहराने की आवश्यकता है कि धारा 55 की उप-धारा (1) का अंतिम भाग स्पष्ट शब्दों में प्रदान करता है कि ऐसी स्थिति में किसी भी न्यायालय के पास ऐसे विवाद के संबंध में किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इस स्थिति को और दोहराने के लिए, अधिनियम की धारा 82(सी) में प्रावधान है कि किसी भी नागरिक या राजस्व न्यायालय के पास

धारा 55 के तहत आवश्यक किसी भी विवाद के संबंध में रजिस्ट्रार को संदर्भित करने या किसी भी मामले में धारा 55 के तहत कार्यवाही के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। ए की शुरूआत की गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि यहां वैधानिक प्रावधान का पूरा जोर धारा 55 में सूचीबद्ध पक्षों के निर्दिष्ट विवादों को केवल नागरिक और राजस्व मामलों के संपूर्ण बहिष्कार के लिए वैधानिक मध्यस्थता के दायरे में लाना है।

12.संपूर्ण धारा 55 के ढांचे पर फिर से एक व्यापक नज़र डालने से सुरक्षा के इस क्षेत्र का विस्तार करने और विवाद की प्रकृति के साथ-साथ इसके पक्षों के संबंध में सिविल और राजस्व न्यायालयों के बहिष्कार के लिए विधायिका की चिंता प्रदर्शित होती है। पूर्व के संबंध में, जीजे.पी. में चागला, जे. (जैसा कि वह तब था) की निम्नलिखित टिप्पणियों को याद करना उचित है। रेलवे कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम भीखा-जी मेरवानजी करंजिया कर्मचारी (4)।

> “अधिनियम की धारा 54 में विधायिका द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों 'किसी सोसायटी के व्यवसाय को छूना' को प्रतिबंधित अर्थ देना सही नहीं है। 'व्यवसाय' शब्द बहुत व्यापक शब्द है और निश्चित रूप से यह किसी समाज की वस्तुओं का पर्याय नहीं है। अभिव्यक्ति 'किसी समाज के व्यवसाय को छूने का मतलब किसी समाज के व्यवसाय को प्रभावित करना या किसी समाज के व्यवसाय से संबंधित होना होगा। हालांकि, ऐसा नहीं है
>
> ' > (4)'एआईआर, 1942 बम। 341. 1 '
>
> नौकरों को नौकरी पर रखना या बर्खास्त करना कंपनी के उद्देश्यों में से एक है, यह ऐसा कुछ है जो वह सामान्य तौर पर करती हैइसके व्यवसाय का क्रम। और क्रम में जो कुछ भी किया जाता है. , व्यवसाय का कोई भी पाठ्यक्रम निश्चित रूप से व्यवसाय से संबंधित या प्रभावित नहीं करता है।'' .

जहां तक संबंधों का संबंध है, विधायिका ने जानबूझकर अपने दायरे में सदस्यों, पासिट सदस्यों, मृत सदस्यों और उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ अधिकारियों, एजेंटों, कर्मचारियों, पिछले कर्मचारियों और उनके नामांकित व्यक्तियों, उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों आदि को भी शामिल किया है। इसलिए, यह उचित प्रतीत होता है कि इस क़ानून के बड़े उद्देश्य को शाब्दिक या संकुचित व्याख्या के विरुद्ध आगे बढ़ाने के लिए विवाद की प्रकृति और उसमें पक्षों की संख्या दोनों के संबंध में धारा 55 की भाषा पर उदार निर्माण किया जाना चाहिए। उसके

13. यहां मामले का मूल धारा 55(1) (बी) में प्रयुक्त वाक्यांश 'किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करना' का आयाम है। यह स्पष्ट है कि जहां तक एक सोसायटी और उसके पिछले सदस्यों के बीच विवाद का सवाल है, वे स्पष्ट रूप से वैधानिक मध्यस्थता के दायरे में हैं। हालाँकि, विधायिका ने जानबूझकर इसे बढ़ाया जब उसने गैर-सदस्यों को भी अपने दायरे में लाने के लिए उपरोक्त वाक्यांश का इस्तेमाल किया। स्पष्ट रूप से रखी गई योग्यता या सीमा यह है कि ऐसे गैर-सदस्य को या तो किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करना चाहिए और एक आवश्यक परिणाम के रूप में उनके माध्यम

से उत्तरदायी होना चाहिए क्योंकि यदि कोई किसी के माध्यम से दावा करता है तो अपरिहार्य कानूनी परिणाम होंगे? कि वह उसके माध्यम से समान रूप से जवाबदेह होगा।

14. याचिकाकर्ता की ओर से इस पर बहस करने की मांग की गई थी। कि वाक्यांश 'दावा (किसी सदस्य, पूर्व सदस्यों या मृत सदस्य के माध्यम से)' केवल हित के हस्तांतरण के मामलों तक ही सीमित होना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप केवल हित में उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे। मैं देने में असमर्थ हूं वाक्यांश की ऐसी कोई भी कृत्रिम ^और संकुचित व्याख्या, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, क़ानून के बड़े उद्देश्य के विपरीत होगी। इस संदर्भ को उप-धारा (1) के खंड (सी) में संदर्भित किया जा सकता है।) पीआई धारा 55।' यह नामांकित व्यक्तियों, उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों के संदर्भ में बात करता है।
इस प्रकार विधायिका वास्तव में इस पृष्ठ के प्रति सचेत थी यदि यह इरादा था कि दावा केवल एक नामांकित व्यक्ति के माध्यम से होना चाहिए,

उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि आदि, तो निश्चित रूप से वही शब्दावली खंड (बी) में भी प्रयोग की गई होगी। ये शब्द कला के प्रसिद्ध शब्द हैं और विधायिका ने जानबूझकर 'दावा' और 'के माध्यम से' शब्दों का उपयोग करने के लिए चुना है और इसलिए, इसे व्यापक सामान्य आयाम की भाषा में शामिल किया है। मुझे इन शब्दों के स्पष्ट और सामान्य अर्थ को कम करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। ऐसे किसी पूर्व सदस्य के हितों के हस्तांतरण या उत्तराधिकारियों-हित में और कानूनी प्रतिनिधियों आदि की बहुत संकुचित और सीमित अवधारणाएँ। एक समान संदर्भ में 'के माध्यम से' शब्द से जुड़ा सही अर्थ कर्ता हम मनसा राम और अन्य बनाम ओम प्रकाश हीरा राम (5) में पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा विचार के लिए आया था। वहां निर्माण के लिए पंजाब प्री-एम्पशन एक्ट की धारा 15(2)(ए) का प्रयोग किया गया। उसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -

> “यह उल्लेख करना उचित है कि प्री-एम्प्शन एक्ट की धारा 15 (2) (ए) में प्रयुक्त शब्द 'के माध्यम से' है जिसका अर्थ है - 'के माध्यम से', 'के कारण', 'के माध्यम से' , 'एजेंसी', 'कारण से', आदि। यह शब्द 'के माध्यम से', इसलिए, व्यापक आयाम का है।

उपरोक्त आधिकारिक व्याख्या के आलोक में मुझे अधिनियम की धारा 55 में प्रयुक्त 'के माध्यम से' शब्द को संकुचित तरीके से समझने या व्यापक आयाम वाले शब्द पर 'कोई कृत्रिम सीमा' लगाने का कोई कारण नहीं दिखता है।

-15.. वाक्यांश का वास्तविक अनुप्रयोग 'सहकारी समिति के संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय को छूता है'। वर्तमान मामला भी उतना ही शिक्षाप्रद है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि विवाद को जन्म देने वाला लेनदेन प्रतिवादी नंबर 3, जगाधरी सहकारी विपणन सोसायटी और इम्बली सोसायटी के बीच था, जो इस मार्केटिंग सोसायटी का सदस्य था। एक सदस्य के रूप में क्षमता. याचिकाकर्ता ने खुद को उर्वरकों की बिक्री और देय कमीशन के संबंध में इम्बली सोसाइटी के सेल्समैन के रूप में दर्शाया और वह इसका एजेंट या भागीदार था। इम्बली सोसायटी को मुस्तफाबाद पार्मर्स कंपनी पेइफ 7®ऑनक्रे^ और सर्विस सोसायटी के साथ

मिला दिया गया है, प्रतिवादी 'नंबर 4. - उत्तरदाताओं संख्या 3 और 4 55(1)'(बी) के बीच विवाद हो सकता है) चूँकि यह एक समाज और ^ के बीच उत्पन्न होता है[5]!?OTfeB9|® किसी सदस्य की क्षमता। एक बार ऐसा हो जाए, तो एक अभिन्न

5.oanimon £ y^से l

और इस विवाद की अविभाज्य शाखा, प्रतिवादी नंबर 4 के एजेंट या भागीदार के रूप में याचिकाकर्ता के खिलाफ मार्केटिंग सोसायटी का दावा है। इसलिए, यह एक सदस्य के माध्यम से किया गया दावा है। यह तर्कसंगत प्रतीत होता है कि एक बार जब मार्केटिंग सोसायटी और मुस्तफाबाद सोसायटी के बीच वैधानिक संदर्भ सक्षम हो जाता है तो सदस्य सोसायटी के माध्यम से निहित कमीशन या अन्य दायित्व जैसे संबंधित दावे भी खंड (बी) के दायरे में होने चाहिए। अन्यथा धारण करना वास्तव में खंड (बी) के उद्देश्य और प्रावधान को पूरी तरह से निरर्थक बना देगा। मेरे विचार में इसे उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों आदि जैसे केवल हित-हस्तांतरण के मामले तक ही सीमित कर दिया जाएगा। .अनिवार्य प्रतीत होता है।

16. यदि स्थिति 'उलट' हो तो मामले को दूसरे कोण से भी देखा जा सकता है। यह याचिकाकर्ता का अपना मामला है कि वह इमबली सोसाइटी के साथ उर्वरक पर कमीशन साझा कर रहा था। मान लीजिए कि इस तरह के कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था, तो मुस्तफाबाद सोसाइटी के माध्यम से इम्बली सोसाइटी स्पष्ट रूप से कमीशन के भुगतान पर विवाद के संबंध में मध्यस्थता का दावा करने की हकदार होगी। याचिकाकर्ता आयोग में समान रूप से दावेदार और हिस्सेदार होगा। क्या यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि खंड (बी) की व्यापक भाषा के बावजूद याचिकाकर्ता को या तो मुस्तफाबाद सोसायटी के माध्यम से ऐसा दावा करने या इसमें शामिल होने से रोक दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए मध्यस्थता के संदर्भ में? उत्तर स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह इतना हकदार होगा।

17. मामले को उस पवित्र सिद्धांत के प्रकाश में देखना भी उतना ही शिक्षाप्रद है कि कानून एक ही उद्देश्य के लिए कार्यवाहियों की बहुलता से घृणा करता है। इसमें इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 3, और 4 दो सहकारी समितियों के बीच मध्यस्थता का संदर्भ, जो परस्पर सदस्य हैं, स्पष्ट रूप से बनाए रखने योग्य होगा और वास्तव में उक्त दावे के लिए कोई भी मुकदमा वर्जित होगा। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क पर, यदि मार्केटिंग सोसाइटी, प्रतिवादी संख्या 3, याचिकाकर्ता के खिलाफ भी दावा करना चाहती है/उसे और इम्बली सोसाइटी को संयुक्त रूप से देय कमीशन के संबंध में उसे एक नागरिक का सहारा लेना चाहिए जहां तक याचिकाकर्ता के खिलाफ दावे का संबंध है और इम्बली सोसायटी के खिलाफ वैधानिक संदर्भ का संबंध है, क्योंकि इस संदर्भ में माना जाता है कि नागरिक क्षेत्राधिकार वर्जित होगा। इसमें स्पष्ट रूप से समानांतर कार्यवाही शामिल है जहां विवाद न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है बल्कि अविभाज्य और अविभाज्य दोनों है। फिर यह नहीं हो सका

हमारे सामने यह विवाद है कि यदि प्रतिवादी संख्या 4 मुस्तफाबाद सोसाइटी को याचिकाकर्ता के खिलाफ उसी कमीशन के भुगतान के संबंध में कोई दावा या विवाद करना है तो वह निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 55 के तहत मध्यस्थता का दावा कर सकती है। इसलिए, एक ही विवाद के लिए, मध्यस्थता के दो अलग-अलग संदर्भ 'खुले' होंगे, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध। इस तरह के विवाद को "किसी सदस्य, पिछले सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करना"

वाक्यांश की स्पष्ट व्याख्या पर एकल मध्यस्थता में हल किया जा सकता है। ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि इसकी संकुचित व्याख्या करके अनेक मध्यस्थताओं और सिविल मुकदमों को बाध्य किया जाए।

18. याचिकाकर्ता की ओर से एक ही विवाद के समाधान के लिए अपनाए गए रुख पर तीन अलग-अलग समानांतर कार्यवाहियों का सहारा लेना होगा। पूरे विवाद को एक ही मध्यस्थता से सुलझाने के बजाय (1) प्रतिवादी संख्या 3 और प्रतिवादी संख्या 4 के बीच मध्यस्थता करनी होगी; और (2) प्रतिवादी संख्या 4 और 3, याचिकाकर्ता के बीच मध्यस्थता और याचिकाकर्ता के खिलाफ मार्केटिंग सोसाइटी (प्रतिवादी संख्या 3) के दावे के प्रयोजनों के लिए सिविल कोर्ट में एक अलग मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। निर्माण के बड़े सिद्धांत पर भी, जहां एक व्याख्या से इस तरह के असंगत परिणाम होने की संभावना है और यह स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक शरारत के रूप में काम करता है, उससे बचा जाना चाहिए और दयालुतापूर्वक अनेक कार्यवाहियों से बचा जाना चाहिए।

19. मुख्य रूप से सिद्धांत और क़ानून के प्रावधानों पर मामले की जांच करने के बाद, उदाहरण के लिए इसे आगे बढ़ाना भी अपरिहार्य है। डेक्कन मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम मेसर्स दलीचंद जुगराज जैन और अन्य) (6) में उनके आधिपत्य ने महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1961 के कुछ हद तक अनुरूप प्रावधान का अर्थ लगाया। मामले के विशेष तथ्यों पर वे समान हैं इस निष्कर्ष पर कि जो पट्टा विवाद का विषय था, वह मूल मालिक द्वारा एक सदस्य के रूप में नहीं बल्कि कब्जे में बंधककर्ता के रूप में निष्पादित किया गया था। इसलिए, किसी सदस्य द्वारा सख्त सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में लेन-देन नहीं किए जाने से पूरा विवाद मध्यस्थता के वैधानिक संदर्भ के दायरे में नहीं आता है। हालाँकि एक में. सदस्यों के माध्यम से दावों का स्पष्ट संदर्भ जहां

.(6)'एआईआर 1969 3.071320.

लेन-देन संदर्भ के दायरे में होगा, इसे स्पष्ट रूप से निम्नानुसार देखा गया है: -

> ♦•♦♦हमें ऐसा लगता है कि इससे पहले कि किसी व्यक्ति को किसी सदस्य के माध्यम से दावा करने के लिए कहा जाए, दावा उस लेन-देन या व्यवहार के माध्यम से उत्पन्न होना चाहिए जिसके साथ सदस्य ने सदस्य के रूप में समाज में प्रवेश किया हो। यदि कोई सदस्य सोसायटी के साथ एक सदस्य के रूप में नहीं बल्कि एक अजनबी के रूप में लेनदेन करता है, तो उसे धारा 91 (1) (ए) या (सी) के प्रावधानों के तहत कवर किया जाना चाहिए। लेकिन जब यह माना जाता है कि मूल लेनदेन सदस्य द्वारा सोसायटी के साथ एक सदस्य के रूप में किया गया था, तो कोई भी व्यक्ति जो उस सदस्य के माध्यम से अधिकारों या शीर्षक का दावा करता है, उसे धारा 91 (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत आना चाहिए।

20. हालाँकि, जो मामला सीधे तौर पर इस मुद्दे को कवर करता है, वह नवजीवन पेपर मार्ट एन. राजकोट* विभाग नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (7) में डिवीजन बेंच का फैसला है। उसमें गुजरात सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा 96(1)(बी) का लगभग समान प्रावधान विचार के लिए गिर गया था। इसमें याचिकाकर्ता ने भी यही रुख अपनाया था कि

चूंकि वह सहकारी समिति का सदस्य नहीं था, इसलिए उसके खिलाफ कोई संदर्भ दावा करने योग्य नहीं था। सिद्धांत और मिसाल पर विस्तृत चर्चा के बाद इस रुख को खारिज करते हुए और मूल रूप से एम (एस डुलिचन जुगराज जैन) के मामले में अनुपात पर भरोसा करते हुए इसे इस प्रकार रखा गया: -

> "उपरोक्त टिप्पणियों में विचार किए गए दावे में गैर-सदस्य के खिलाफ किया गया दावा भी शामिल होगा * यदि किसी गैर-सदस्य के खिलाफ किया गया दावा एक लेनदेन के माध्यम से उत्पन्न होता है, जिसे सदस्य ने सदस्य के रूप में सोसायटी के साथ दर्ज किया है, तो गैर-सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है धारा 96 के अंतर्गत इसके विरुद्ध है, बशर्ते कि गैर-सदस्य वह व्यक्ति हो जो उस सदस्य के माध्यम से अपने अधिकारों या स्वामित्व का दावा करता हो।

21. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उपरोक्त मामले के औचित्य पर कोई सार्थक चुनौती नहीं उठाई जा सकी। एकमात्र निवेदन यह था कि यह एक मामला था

(7) AIR~1975 गुजरात 18."~

जहां विवादित संपत्ति, अर्थात् एक प्रिंटिंग मशीन, सहकारी समिति के पास गिरवी रखी गई थी। यह मुझे बिना किसी भेद के एक भेद प्रतीत होता है। पूरे फैसले की निकटतम जांच से पता चलेगा कि फैसले में इस पहलू पर दूर-दूर तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। इसमें तर्क का मूल गुजरात अधिनियम की धारा 96(1)(बी) के वाक्यांश पर आधारित है, जो किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या सोसायटी के मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के संबंध में है, जैसा कि हमारे सामने मामला है। मैं गुजरात मामले में तर्क की शैली से निःसंकोच सहमत हूं और उसका पालन करूंगा।

22. यह अभी भी बाकी है कि कुछ अंतर-अदालत, दृष्टिकोण की असंगति पर कैसे विचार किया जाए जिसके कारण वास्तव में बड़ी बेंच को संदर्भित करना आवश्यक हो गया था। हालाँकि, यह केवल प्रस्ताव चरण में की गई संक्षिप्त टिप्पणियों के संदर्भ में है। इंद्रजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य में, (8) हमारे सामने लगभग समान बिंदु विचार के लिए आया था, हालांकि प्रस्ताव चरण में। संक्षिप्त आदेश के संदर्भ से संकेत मिलेगा कि मामले पर पीठ के समक्ष पर्याप्त बहस नहीं हुई। धारा 55(1)(बी) के विशिष्ट प्रावधान पर शायद पार्टियों के वकील ने भरोसा नहीं किया था और बेंच द्वारा इसकी दूर-दूर तक चर्चा भी नहीं की गई थी। विशेष रूप से किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने के महत्वपूर्ण मुद्दे पर न तो कोई हलचल हुई और न ही उस पर कोई टिप्पणी की गई। परिणामस्वरूप, इस संदर्भ में बड़े सिद्धांतों का संदर्भ नहीं दिया जा सका और न ही संबंधित प्राधिकारियों का, जिनकी ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है। मुझे अत्यंत सम्मान के साथ यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त कारणों से इंद्रजीत सिंह का मामला कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है और इसे खारिज कर दिया गया है।

23. नरपत सिंह बनाम सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (9) में ओसी रेड्डी और एमआर शर्मा, जे जे की संक्षिप्त टिप्पणियों का भी संदर्भ दिया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि धारा 55 को ध्यान में रखते हुए इसके खिलाफ कोई पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। एक ऋणी सोसायटी का कर्मचारी। उसमें मौजूद तथ्यों से संकेत मिलता है कि क्रेडिटर

सोसाइटी एक सदस्य के रूप में कार्य करने वाले सदस्य के माध्यम से सेल्स मैन के खिलाफ दावा नहीं कर रही थी। इसलिए, धारा 55(1)(बी) न तो आकर्षित हुई और न ही इसे दूर से ही विज्ञापित किया गया

(8) 1981 के सीडब्ल्यू 414 का निर्णय 23-3-1981 को हुआ।
(9) 1976 पीएक्स.जे. 522.

बेंच। इसलिए, नरपत सिंह का मामला मुझे इस सीमित बिंदु पर अलग लगता है कि एक ऋणग्रस्त सोसायटी का कर्मचारी वास्तव में अधिनियम की धारा 55 के दायरे में नहीं है।

24. उपरोक्त दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से बाद के डिवीजन बेंच के फैसले की टिप्पणियों से पुष्ट होता है, जिसमें शर्मा जे. सदस्य थे, जिसे अमर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (10) के रूप में रिपोर्ट किया गया था। उसमें नरपत सिंह के मामले (सुप्रा) का उल्लेख करने के बाद इसे इस प्रकार रखा गया: -

> ''याचिका में की गई शिकायत यह है कि पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 (इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 56 के तहत नियुक्त मध्यस्थ द्वारा प्राथमिक सोसायटी के एक सेल्समैन के खिलाफ और के पक्ष में एक पुरस्कार दिया गया है। सेंट्रल सोसायटी. श्री नरपत सिंह बनाम सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां और अन्य (11) के आधार पर यह तर्क दिया गया है कि प्राथमिक सोसायटी और केंद्रीय सोसायटी के सेल्समैन के बीच विवाद को रजिस्ट्रार द्वारा मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है।
>
> 2. उत्तरदाताओं की ओर से दाखिल लिखित बयान देखे गए हैं। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता प्राथमिक सोसाइटी का सदस्य था, यानी प्रतिवादी नंबर 5, जो बदले में सेंट्रल सोसाइटी का सदस्य था, यानी प्रतिवादी नंबर 3. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 5 के माध्यम से अपने अधिकार का दावा किया। नतीजतन, उनका मामला अधिनियम की धारा 55(1)(बी) के अंतर्गत आता था और निर्णय के लिए विवाद का संदर्भ क्रम में था। इन परिस्थितियों में, हम इस याचिका में कोई ताकत नहीं देखते हैं और इसे खारिज करने का आदेश देते हैं।''

मैं उपरोक्त बातों से पूरी तरह सहमत हूं, टिप्पणियां संक्षिप्त हैं, और पहले दर्ज किए गए विस्तृत कारणों के आधार पर बिना किसी हिचकिचाहट के उक्त दृष्टिकोण की पुष्टि करूंगा।

25. निष्कर्ष निकालने के लिए शुरू में पूछे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया गया है और यह माना जाता है कि एक विवाद है

(10)1978 पीएलजे 46.~~ ~'
(11) 1976 पीएलजे 522।

एक ओर सहकारी समिति और दूसरी ओर सहकारी समिति के कर्मचारी, एजेंट या सदस्य के बीच धारा 55(1) (बी) के तहत मध्यस्थता के दायरे में होगा, जहां किया गया दावा किसी व्यक्ति के माध्यम से किया गया है या एक सोसायटी जो बदले में दावेदार-सोसाइटी का सदस्य है।

26. जैसा कि पहले देखा गया है, याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया एकमात्र मुद्दा उपरोक्त उत्तर से उसके खिलाफ समाप्त हो गया है। कोई अन्य नहीं; बिंदु पर आग्रह किया गया था. इसलिए, रिट याचिका निराधार है और इसे खारिज किया जाता है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

*सपा*गोयल, जे.-

27. मैंने अपने विद्वान भाई, मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए निर्णय का अध्ययन किया है, लेकिन अत्यंत सम्मान के साथ मुझे उससे सहमत होने में असमर्थता पर खेद है।

28. याचिका में आरोप लगाए गए तथ्य यह हैं कि इम्बली कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटी, लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व अब प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा किया जाता है, मुस्तफाबाद फार्मर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड (इसके बाद इसे इम्बली सोसाइटी कहा जाएगा) कंसाइनमेंट के आधार पर उर्वरकों की खरीद करती थी। जगाधरी सहकारी विपणन-सह-प्रसंस्करण सोसायटी, लिमिटेड, जगाधरी (संक्षेप में जगाधरी सोसायटी कहा जाता है) से और सहमत दर पर इसकी बिक्री पर कमीशन प्राप्त करें। इसने याचिकाकर्ता, मैम राज को जगाधरी सोसायटी से उर्वरक प्राप्त करने और इसकी बिक्री को प्रभावित करने के लिए अपना सेल्समैन नियुक्त किया। याचिकाकर्ता को कोई निश्चित वेतन नहीं दिया गया था, लेकिन इम्बली सोसायटी के साथ हुए समझौते के तहत उसे इम्बली सोसायटी द्वारा अर्जित कमीशन का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाना था। समझौते के तहत याचिकाकर्ता को बिक्री आय सीधे जगाधरी सोसायटी के पास जमा करने की आवश्यकता थी। उर्वरकों की कीमत के कारण कुछ राशि का भुगतान नहीं किया गया, जगाधरी सोसायटी ने अपने विवाद को निपटाने के लिए पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 (संक्षेप में अधिनियम कहा जाता है) की धारा 55 के तहत सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को स्थानांतरित कर दिया, जिन्होंने भुगतान किया। रुपये की राशि का पुरस्कार. 16,721 में याचिकाकर्ता और इम्बली सोसाइटी को इसके भुगतान के लिए अलग-अलग और संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है और निर्देश दिया गया है कि राशि पहले याचिकाकर्ता से वसूल की जाए। याचिकाकर्ता ने फैसले के खिलाफ अपील की और इसे मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी कि नहीं

अधिनियम की धारा 55 के तहत संदर्भ उनके और जगाधरी सोसायटी के बीच सक्षम था, उनकी अपील को सरकार के संयुक्त सचिव ने खारिज कर दिया था जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की गई थी।

29. प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा दायर लिखित बयान में, याचिकाकर्ता का यह दावा कि वह एक सेल्समैन था और इम्बली सोसाइटी द्वारा नियोजित था, को अस्वीकार कर दिया गया और यह कहा गया कि पार्टियों के बीच समझौते के अनुसार, वह बिक्री पर कमीशन प्राप्त करता था। उर्वरक. हालाँकि, मध्यस्थ के समक्ष यह दलील नहीं दी गई कि याचिकाकर्ता उक्त सोसायटी के सेल्समैन के अलावा कुछ भी था और पूरा पुरस्कार उसी आधार पर आगे बढ़ता है। मध्यस्थ ने याचिकाकर्ता और इम्बली सोसाइटी के बीच हुए समझौते का भी हवाला दिया है जिसके तहत उन्होंने रुपये की सुरक्षा भी प्रदान की थी। सेल्समैन के रूप में नियुक्त होने पर 10,000 रु. अपीलीय आदेश में ही याचिकाकर्ता को सोसायटी का सेल्समैन और पार्टनर बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि "साझेदार" शब्द का प्रयोग अपीलीय प्राधिकारी द्वारा शिथिल रूप से किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता को कोई निश्चित वेतन नहीं दिया जाना था और बिक्री पर अर्जित कमीशन साझा करना था। अन्यथा अपीलीय आदेश में याचिकाकर्ता को सोसायटी के साथ भागीदार बनाए रखने के लिए कोई तथ्य या कारण नहीं दिए गए हैं। यदि याचिकाकर्ता सोसायटी में भागीदार था तो वह उसी समय उसका सेल्समैन नहीं हो सकता था। अपीलीय आदेश में "साझेदार" शब्द के उपयोग का संकेत लेते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 ने पहली बार लिखित बयान में दलील दी कि याचिकाकर्ता उर्वरकों की बिक्री में सोसायटी के साथ भागीदार था। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 4, सोसायटी के पास याचिकाकर्ता के साथ निष्पादित समझौते का अधिकार था, लेकिन उसने कभी भी इसे लिखित बयान के साथ प्रस्तुत करने का विकल्प नहीं चुना, जो पार्टियों के बीच संबंधों की प्रकृति को दिखा सके। समझौते के अभाव में, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 4 के बीच संबंध उनके बीच स्वीकृत तथ्यों पर निर्धारित किया जाना है और कोई भी निष्कर्ष केवल लिखित बयान या शब्द के उपयोग के आधार पर नहीं निकाला जा सकता है। *एर'' अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश में।

30. याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 4 के बीच वास्तविक संबंध के संबंध में स्वीकार किए गए तथ्य इम्बली सोसाइटी ने एक लिखित समझौते के माध्यम से याचिकाकर्ता को नियुक्त किया है।

इसके सेल्समैन ने उसे जगाधरी सोसायटी से उर्वरकों की डिलीवरी लेने, इसकी बिक्री को प्रभावित करने और बिक्री आय को सीधे जगाधरी सोसायटी में जमा करने के लिए अधिकृत किया। इस सारे काम के लिए, उन्हें जगाधरी सोसायटी से उर्वरकों की बिक्री पर इम्बली सोसायटी द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक के बजाय प्राप्त कमीशन को समान रूप से साझा करना था। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कभी भी उर्वरकों की बिक्री में भागीदार के रूप में इम्बली सोसाइटी में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि केवल कमीशन के 50 प्रतिशत के भुगतान पर पूर्व की ओर से बिक्री को प्रभावित करने के लिए सेल्समैन या एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। जगाधरी सोसायटी से प्राप्त किया जा सकता है।

31. पार्टियों के बीच विवाद अधिनियम की धारा 55 के खंड (बी) में "सदस्य के माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति" शब्दों की व्याख्या पर केंद्रित है। इस धारा के तहत, सहकारी समिति के व्यवसाय से संबंधित किसी भी विवाद को एक मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है यदि यह समिति, उसके सदस्यों और चार खंडों (ए) से (डी) में उल्लिखित अन्य व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह उक्त किसी भी धारा के अंतर्गत नहीं आता है और इस प्रकार उसके खिलाफ किसी भी संदर्भ का दावा नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रतिवादी के अनुसार, उसका मामला खंड (बी) के तहत आता है, वह एक सदस्य के माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति है। यानि, इम्बली सोसायटी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि इम्बली सोसायटी जगाधरी सोसायटी की सदस्य थी। धारा 55 और खंड (बी) के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं: -

> “55. ऐसे विवाद जिन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।
>
> (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सहकारी समिति के गठन, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है:-
>
> (a) ****
>
> (b) किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति और सोसायटी, उसकी समिति या सोसायटी के किसी अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी या परिसमापक, अतीत या वर्तमान के बीच, या
>
> (c) ****
>
> (d) *****

खंड (बी) और सटीक शब्दों के समान प्रावधान, एक सदस्य के माध्यम से दावा" सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार के लिए आया। मेरे विचार से यह मामला डेक्कन मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक डीटीडी के फैसले से समाप्त हो गया है। बनाम मिस दलीचंद जुगरा जैन और अन्य, (12), यह बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील थी, जिसने महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 91 में "एक सदस्य के माध्यम से दावा" शब्दों की व्याख्या करते हुए, 1961, निम्नानुसार शासन किया गया:-

> "शब्द, 'किसी सदस्य के माध्यम से दावा करना* को उनका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए, अर्थात, किसी सदस्य के माध्यम से शीर्षक या अधिकार प्राप्त करना। साथ ही 'सदस्य' शब्द को महत्व दिया जाना चाहिए और दावा किया गया शीर्षक या अधिकार वे होने चाहिए जिनके लिए एक सदस्य हकदार था या जिसे वह सदस्य होने के आधार पर दावा कर सकता था। इसलिए 'किसी सदस्य के माध्यम से दावा करना' शब्द का अर्थ किसी सदस्य के माध्यम से ऐसी उपाधि या अधिकार प्राप्त करना है जो सदस्य के पास था या उसने सदस्य होने के कारण या सदस्य के रूप में अपनी क्षमता के कारण अर्जित किया था।''

उच्चतम न्यायालय द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को निम्नलिखित शब्दों में अनुमोदित किया गया:-

> "*♦*♦**ऐसा लगता है
>
> हमें (इससे पहले कि किसी व्यक्ति को किसी सदस्य के माध्यम से दावा करने के लिए कहा जा सके, दावा एक लेनदेन या लेनदेन के माध्यम से उत्पन्न होना चाहिए जो सदस्य ने एक सदस्य के रूप में सोसायटी के साथ किया था। यदि किसी सदस्य ने सदस्य के रूप में नहीं बल्कि सोसायटी के साथ कोई लेनदेन किया है लेकिन एक अजनबी के रूप में, उसे, यदि बिल्कुल भी, धारा 91 (1) (ए) या (सी) के प्रावधानों द्वारा कवर किया जाना चाहिए। लेकिन एक बार यह माना जाता है कि मूल लेनदेन सदस्य द्वारा किया गया था एक सदस्य के रूप में समाज तो कोई भी व्यक्ति जो उस सदस्य के माध्यम से अधिकारों या शीर्षक का दावा करता है उसे धारा 91(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत आना चाहिए।

हालाँकि उस मामले में मुख्य जोर इस तथ्य पर दिया गया था कि सदस्य ने सोसायटी के साथ एक सदस्य के रूप में नहीं बल्कि एक अजनबी के रूप में लेन-देन किया था, लेकिन फिर भी, "सदस्य के माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति" शब्द का अर्थ एक व्यक्ति बताया गया था। जो ऐसे सदस्य के माध्यम से अधिकार या स्वामित्व का दावा करता है।

(12) एआईआर 1969 एससी 1320।' ~

(32) वर्तमान मामले के तथ्यों पर इस परीक्षण को लागू करने से पहले, यह भी देखा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 55 संबंधित पक्षों के किसी भी अधिकार या देनदारियों को बनाती, घोषित या मान्यता नहीं देती है, बल्कि केवल विवादों को तय करने के लिए एक वैकल्पिक मंच प्रदान करती है। उन्हें। विवाद को जन्म देने वाले अधिकारों और देनदारियों की नींव देश के सामान्य कानून या अधिनियम के प्रावधानों पर होनी चाहिए।

(33) अब वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हुए, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता को उर्वरकों की बिक्री पर अर्जित कमीशन के आधे भुगतान पर इमबली सोसाइटी द्वारा सेल्समैन के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे जगदबरी सोसाइटी से इसकी डिलीवरी लेने के लिए अधिकृत किया गया था। इसकी ओर से. याचिकाकर्ता के साथ अपने समझौते से इम्बली सोसाइटी ने कभी भी जगाधरी सोसाइटी के साथ समझौते के तहत देनदारियों के अपने किसी भी अधिकार को हस्तांतरित नहीं किया। इम्बली सोसाइटी के साथ अपने समझौते के आधार पर, याचिकाकर्ता ने कोई अधिकार हासिल नहीं किया। दो सोसाइटियों के बीच अनुबंध के तहत देयता और इस प्रकार वह न तो उर्वरकों की बिक्री आय के लिए जगाधरी सोसाइटी को खाते देने के लिए उत्तरदायी था और न ही इससे कमीशन के अपने हिस्से का दावा करने का हकदार था। वह जगाधरी सोसायटी को उर्वरकों की डिलीवरी के लिए मजबूर नहीं कर सकता था या इम्बली सोसायटी के साथ अनुबंध के उल्लंघन के लिए नुकसान के लिए कोई दावा नहीं कर सकता था। उन्हें केवल अधिकृत एजेंट के रूप में कार्य करना था और इम्बली सोसाइटी द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना था। अपनी ओर से कर्तव्य में किसी भी लापरवाही या कदाचार या कदाचार के लिए, वह केवल अपने नियोक्ता, या प्रिंसिपल यानी इम्बली सोसाइटी के प्रति जवाबदेह था। चूँकि वह न तो दो सोसाइटियों के बीच हुए समझौते के तहत कुछ भी दावा कर सकता था और न ही उक्त समझौते के आधार पर जगाधरी सोसाइटी को उर्वरकों की कीमत के भुगतान के लिए उत्तरदायी था, इसलिए उसे "सदस्य के माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति" नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, अधिनियम की धारा 55 के खंड (बी) द्वारा कवर नहीं किया जाएगा।

(34) दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में नवजीवन-पेपर मार्ट, राजकोट बनाम राजकोट विभाग नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट, (सुप्रा) पर भरोसा किया कि याचिकाकर्ता "दावा करने वाला व्यक्ति" होगा। एक सदस्य।" हालाँकि, यह निर्णय तथ्यों के आधार पर भिन्न है और इसका वर्तमान मामले पर प्रभाव पड़ता है। वहाँ, सहकारी के एक सदस्य

सोसाइटी ने एक सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करके उस ऋण के संबंध में बैंक के पक्ष में उस मशीन पर शुल्क बनाकर एक मशीन खरीदी थी। बाद में उसने बंधक मशीन 'सी' को बेच दी जो सहकारी समिति का सदस्य नहीं था। इन तथ्यों पर यह माना गया कि मशीन के संबंध में हाइपोथिकेशन के प्रवर्तन के विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है और 'सी* जो सदस्य के माध्यम से दावा कर रहा था, उसने धारा 96(1) के तहत विवाद में एक पक्ष बनाया (बी) और रजिस्ट्रार के नामांकित व्यक्ति के पास उसके द्वारा खरीदी गई बंधक संपत्ति की सीमा तक उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र था - जाहिर है, 'सी' ने सोसायटी के एक सदस्य के माध्यम से बंधक मशीन का शीर्षक प्राप्त किया था और उसका उत्तराधिकारी था -दिलचस्पी। इसलिए, वह मामला पूरी तरह से मेसर्स दलीचंद जुगराज जैन के मामले (सुप्रा) में निर्धारित नियम के अंतर्गत आता था। इसी प्रकार, उत्तरदाताओं द्वारा उठाया गया एक और तर्क कि यदि याचिकाकर्ता वर्तमान संदर्भ में शामिल नहीं हुआ है, तो इससे कार्यवाही की बहुलता हो जाएगी, जहां तक उक्त खंड (बी) की व्याख्या का संबंध है, न ही इस तरह के विचार का कोई परिणाम नहीं है। , इसकी भाषा को इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है कि इसके दायरे में उन व्यक्तियों को लाया जा सके जो अन्यथा इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। टाली जाने वाली शरारत भी इतनी बड़ी नहीं है कि क़ानून की भाषा को बढ़ाने की आवश्यकता हो क्योंकि दो अलग-अलग संदर्भ, एक जगाधरी सोसाइटी द्वारा इम्बली सोसाइटी के खिलाफ और दूसरा बाद में याचिकाकर्ता के खिलाफ एक साथ आगे बढ़ सकते हैं और हो सकते हैं। एक साथ निस्तारण किया गया।

(35) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा अधिनियम की धारा 55 के उद्देश्य और खंड (बी) की व्याख्या करने की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया ताकि उस उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। जाहिर है, धारा 55 का उद्देश्य सहकारी समितियों को सिविल न्यायालयों में लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी से बचाना है और उनके बीच या इसके चार खंडों में सूचीबद्ध अन्य व्यक्तियों के बीच विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता के माध्यम से त्वरित उपचार प्रदान करना है। . यह मेरी समझ से परे है कि इस तर्क का मौजूदा प्रश्न पर क्या असर है या किस तरह से उक्त धारा का उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जगाधरी सोसायटी के उदाहरण पर किसी संदर्भ का दावा नहीं किया जा सकता है। जगाधरी और इमबली सोसायटी के बीच उर्वरक आपूर्ति और उसकी कीमत के भुगतान के समझौते से उपजा विवाद, क्योंकि किसी भी मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ इमबली सोसायटी का दावा

खंड (बी) और उसके दायित्व को निर्धारित करने के लिए उसके विरुद्ध सक्षम संदर्भ द्वारा कवर किया जाएगा।

उपरोक्त कारणों से, जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, यह याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और विवादित पुरस्कार रद्द कर दिया गया है।

डीएस तेवतिया, जे,-

(36) मुझे माननीय मुख्य न्यायाधीश और एसपी गोयल, जे के फैसले को पढ़ने का सौभाग्य मिला है। मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश के विचार से सहमत हूं।

न्यायालय का आदेश.

(37) बहुमत के दृष्टिकोण के अनुसार, रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।

लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

एसएस संधावालिया, सीजे

डीएस तेवतिया, जे.

एसपी गोयल, जे.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी , हरियाणा